THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (c) Pakistan has *inter-alia* established various camps in its territory and also close to the border, to provide indoctrination, training in handling sophisticated arms and equipment, and for launching of misguided Kashmiri Youth and other fundamentalist terrorist elements into the State. Government is aware of these activities of Pakistan and has consistently urged them to desist from the same, apart from taking up the matter at the international/diplomatic level. Necessary steps are also being taken to meet this challenge by maintaining constant vigil on the LOC/Border and sustained pressure on the terrorists in the interior.

मतदाता सूचियों से विदेशियों के नाम हटाया जाना

1614. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मतदाता सूचियों में से विदेशियों के नाम हटाने का काम चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम कितना पूरा हो चुका है; और

(ग) मतदाता सूचियों में से कितने नाम हटाए जा चुके हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) केवल भारतीय नागरिक ही निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए पात्र हैं। निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का आवधिक रूप से गहन पुनरीक्षण किया जाता है। निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य कुछ राज्यों में चल रहा है। निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान विशेष सावधानी बरती गई है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र व्यक्ति ही निर्वाचक के रूप में नामांकित किए गए हैं और किसी भी अपात्र व्यक्ति को नामांकन नहीं किया गया है, तथापि, निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण करना एक निरंतर प्रक्रिया है और जब कभी भी किसी गलती का पता चलता है, तो सुधारने के लिए कार्रवाई की जाती है।

(ग) गहन पुनरीक्षण के समय निर्वाचक नामावलियां नए सिरे से तैयार की जाती हैं। अत: किसी पूर्ववर्ती निर्वाचक नामावली से नामों को हटाए जाने की बाबत जानकारी नहीं रखी जाती है।

Business Bureau to help consumers

1615. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the 'Indian Express' of the 28th January, 1995 under the caption "Better Business Bureau to help consumer get justice;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) Yes, Sir. As per the press report, a non-governmental organisation in West Bengal has taken initiative to sort out consumer complaints outside the consumer redressal fora. Many such organisations are functioning in the country to help consumer seek redressal of their grievances without taking recourse to legal procedures. All the State Governments/UTs have been advised to take all steps to ensure smooth functioning of the consumer fora. Besides, one time assistance of Rs. 61 crores has been sanctioned by the Planning Commission for disbursal to the State Governments/UTs for strengthening consumer courts so that these can function more effectively.